मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

यह RBI के द्वारा निर्मित एक नीति है, जिसे RBI प्रयोग करके मुद्रास्फीति अर्थात् मुद्रा-आपूर्ति को नियंत्रित करती है।

★ भारत में मौद्रिक नीति को तय करने का कार्य MPC के द्वारा किया जाता है।

<u>**मौद्रिक नीति समिति (MPC)**</u>– इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधि. 1934 के खण्ड 45 - ZB के अंतर्गत रखा गया है। (2016)

★ इस समिति के गठन के पूर्व RBI के गवर्नर, उप-गवर्नर एवं RBI की तकनीकी सलाहकार समिति और अन्य विशेषज्ञों के परामर्श से नीतिगत ब्याज-दर तय करते थे। लेकिन 2016 के बाद से MPC के द्वारा तय किया जाता है।

<u>**MPC की संरचना**</u>– इसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के सदस्य एवं 3 सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य।

RBI – Governor (MPC अध्यक्ष), उप-गवर्नर, (MPC का प्रभारी) एवं 1 अन्य RBI का सदस्य

Note : सरकार के द्वारा मनोनीत 3 सदस्य 4 वर्षों के लिए होते हैं।

★ कम से कम वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य हैं।

★ जब निर्णय बराबरी पर हो, तो RBI के Governor के पास निर्णायक मत होता है।

★ MPC के सदस्यों की नियुक्ति नहीं होती है।

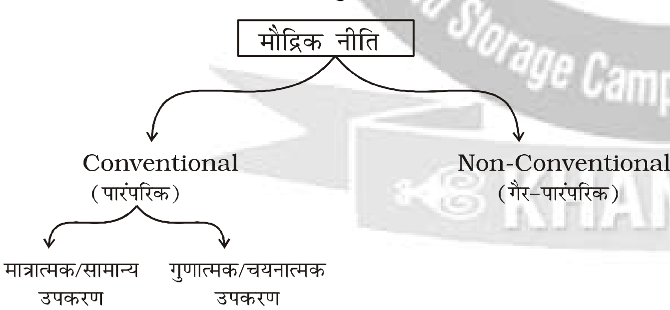

मात्रात्मक / सामान्य उपकरण–

1. Bank Rate (बैंक दर)
2. चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)– Liquidity Adjustment Facility
   (a) Repo Rate (रेपो दर)
   (b) Reverse Repo Rate (विपरीत रेपो दर)
3. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) – Margin Standing Facility
4. आरक्षित अनुपात (Reserve Ratio)
   (a) नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – Cash Reserve Ratio)
   (b) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) – Statutory Liquidity Ratio
5. खुला बाजार संचालन (Open Market Operation)
6. स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility))

1. <u>**Bank Rate (बैंक दर)**</u> – यह वह दर है जिस पर RBI सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

2. <u>**Repo Rate (रेपो दर)**</u> – यह वह ब्याज दर है, जिस पर RBI सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूति के बदले अल्पकालिक ऋण देती है। इसे 1992 में प्रारंभ किया गया।

   Repo — Repurchase Option

⇒ बैंक दर का प्रयोग एक प्रकार से Penalty के रूप में किया जाता है।

3. <u>**सीमांत स्थायी सुविधा [Margin Standing Facility (MSF)]**</u> —

★ 2011 में प्रारंभ किया गया।

★ इसके द्वारा Banks, RBI से एकरात्रि पर्यनत (Overnight) ऋण लेती है। यह बैंकों के NDTL का अधिकतम 2% होता है।

★ यह 1 Cr. या गुणांक में होता है।

★ यह Bank Rate के बराबर अर्थात् Repo Rate से 25 Bps अधिक होता है।

4. <u>**Reverse Repo Rate (विपरीत रेपो दर)**</u>– वह दर जिस पर RBI बैंकों से उधार लेती है। अर्थात् बैंकों का अधिशेष धन अपने पास रखती है एवं बैंकों को प्रतिभूति देती है।

★ 1996 से प्रारंभ हुआ।

5. <u>**स्थायी जमा सुविधा [Standing Deposit Facility (SDF)]:**</u>–

★ प्रारंभ (Launched) 2022

★ 2018 में RBI Act – Section 17 में संशोधन हुआ।

★ जिस दर पर RBI बैंकों से बिना प्रतिभूति के ऋण लेती है।

6. <u>**आरक्षित अनुपात**</u>–

   (a) <u>नकद आरक्षित अनुपात Cash Reserve ratio (CRR)</u>– इसे RBI Act. 1934, खण्ड 42(2) के तहत रखा गया है।

★ प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल मांग एवं समय जमाओं (TDTL) का न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास रखना होता है और यह अनिवार्य है।

★ इस पर RBI कोई ब्याज नहीं देता।

★ यह Cash के रूप में जमा होता है।

★ पहले यह न्यूनतम 3% एवं अधिकतम 15% होता था लेकिन 2006 से यह सीमा समाप्त कर दी गयी।

(b) **<u>वैधानिक तरलता अनुपात [Statutory Liquidity Ratio (SLR)]</u>** – यह बैंकिंग संचालन अधिनियम 1949 खण्ड-24 में वर्णित है।

★ प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL (Net Demand & Time Liability) का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना होता है।

★ यह नकद एवं तरल परिसंपत्ति (Gold, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा आदि) के रूप में रखना होता है।

6. **<u>मुक्त बाजार प्रचालन</u>** – सरकार की प्रतिभूतियों को RBI एवं बैंकों के बीच खरीदना एवं बेचना।

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय

1. **<u>सीमांत आवश्यकता (Margin Requirement)</u>** – बैंकों द्वारा RBI को दी गयी प्रतिभूति के मूल्य एवं RBI द्वारा बैंकों को दिये जाने वाले ऋण के बीच का अंतर।
2. **<u>ऋण नियतन अर्थात् साखों की राशीनिंग (Rationing of Credit)</u>** – RBI द्वारा बैंकों की विभिन्न गतिविधीयों अर्थात् अलग-अलग ऋणों की सीमा को तय करना। जैस- RBI द्वारा बैंकों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण से संबंधित नियम बनाना।
3. **<u>उपभोक्ता ऋण विनिमन (Consumer Credit Regulation)</u>** – RBI बैंकों के द्वारा उनके ग्राहकों को दिये जाने वाले ऋण संबंधी नियम-कानून बनाता है।

   Note : जिस दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है, वह स्वयं Bank के द्वारा तय किया जाता है।
4. **<u>नैतिक दबाव और सुझाव</u>** (Moral Pressure/ Suasion) – RBI के द्वारा बनायी गयी नीतियों को बैंकों द्वारा अनुपालन करवाना।
5. **<u>प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action)</u>** – यदि बैंकें RBI की नीतियों का पालन नहीं करती हैं तब RBI के पास बैंकों के लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार होता है या बैंकों पर किसी प्रकार की Penalty भी लगा सकती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 – 05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है?
(a) 2010–11 (b) 2011–12
(c) 2012–13 (d) 2013–14
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ उपर्युक्त में से एक से अधिक

63 rd BPSC (Pre.) Exam 2017

2. निम्नलिखित में से कौन ' औद्योगि कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) निकालात है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) आर्थिक कार्य विभाग
(c) श्रम ब्यूरो
(d) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

3. उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है–
(a) उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के और परिवर्तन को।
(b) उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को।
(c) उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
(a) भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है।
(b) मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
(c) घटा हुआ मुद्रा परिचलन (मनी सर्कुलेशन), मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।
(d) बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–
1. मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुँचाती है।
2. मुद्रास्फीति बॉण्ड-धारकों को लाभ पहुंचाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

6. निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है?
(a) साहूकार (b) ऋणी
(c) बचत खाता एकाउंट रखने वाले
(d) राजकीय पेंशनर

7. निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +/-2 प्रतिशत के सहनीय स्तर के साथ चार प्रतिश का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है?
(a) भारतीय रिजर्व बैंक (b) भारत सरकार
(c) नीति आयोग (d) चौदहवां वित्त आयोग

8. निम्नलिखित में से कौन-सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीतिकारक हो सकता है?
(a) सार्वजनिक ऋण की चुकौती
(b) बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना
(c) बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना
(d) बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना